वन ट्रिलियन डालर अर्थव्यवस्था के लिए अनिगमित क्षेत्र के उद्यमों का होगा सहयोग

जागरण संवाददाता, वाराणसी : जिले में अनिगमित क्षेत्र की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया जाता है। इस कारण उनके योगदान को प्रदेश की अर्थव्यवस्था में नहीं आंका जाता है। इसके लिए जनपदों की आर्थिक स्थिति के आकलन के लिए शासन ने बाटम अप पद्धति अपनायी है। इसके तहत उत्तर प्रदेश को "वन ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाए जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में अनिगमित क्षेत्र के उद्यमों का सर्वेक्षण (एएसयूएसई) कराया जा रहा है।

इस सर्वेक्षण के लिए जिला प्रशिक्षण केंद्र परिसर में सर्वे के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय

सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ), एमओएसपीआइ भारत सरकार द्वारा निर्धारित पद्धति तथा मार्गदर्शन में कराया जा रहा है। वर्तमान में 75 जिलों के सकल जिला घरेलू उत्पाद के अनुमान टाप डाउन पद्धति से आंकलित किए जा रहे हैं। इसमें राज्य स्तर के अनुमानों को क्षेत्रीय संकेतांकों के आधार पर जनपदों को आवंटित किया जाता है। एएसयूएसई सर्वेक्षण में विनिर्माण, व्यापार तथा सेवा क्षेत्र के अनिगमित उद्यमों से महत्वपूर्ण सूचनायें आदि एकत्रित किया जाएगा। इन सर्वेक्षणों से प्राप्त अनुमानों का प्रयोग जिला घरेलु उत्पाद के अनुमान तैयार करने में किया जाएगा। जो राज्य हेतु नीति निर्माण में अत्यंत उपयोगी होंगे। राज्य में प्रथम बार यह सर्वेक्षण टेबलेट पर केपी साफ्टवेयर के माध्यम से कराया जाएगा। प्रशिक्षण का शुभारंभ मंडलीय उपनिदेशक अर्थ एवं संख्या डीके सिंह द्वारा किया गया। इस दौरान वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर व चंदौली के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी उपस्थित रहे। प्रशिक्षण में तकनीकी पहलुओं के संबंध में अरुण कुमार तिवारी एवं धर्मपाल शास्त्री, वरिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी एनएसओ ने जानकारी दी।